वेदांता ने नेट-जीरो ट्रांजिशन के लिए 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल 52% बढ़ा

ET hindi.economictimes.com/news/vedanta-invests-over-1-billion-dollar-in-net-zero-transition-renewable-energy-use-rises-52-percent-2030-target/amp_articleshow/133350209.cms

Abhisek Tripathi August 19, 2026

माइनिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी Vedanta ने नेट-जीरो की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने बताया कि पिछले 5 साल में उसने नेट-जीरो ट्रांजिशन से जुड़ी पहलों पर 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया। कंपनी का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने, कम कार्बन वाले ईंधन अपनाने, एनर्जी की बचत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए कार्बन उत्सर्जन कम करने पर है। इस दिशा में वेदांता के ग्रुप स्तर पर वित्त वर्ष 2025-26 रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल सालाना आधार पर 52% बढ़कर 4 बिलियन यूनिट यानी 400 करोड़ यूनिट हो गया। कंपनी के मुताबिक, यह बिजली करीब 3 करोड़ भारतीय घरों की एक साल की बिजली खपत के बराबर है। फिलहाल वेदांता के पास करीब 2,000 MW की इंस्टॉल्ड और कॉन्ट्रैक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली 2.5 GW रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करना है।

डिकार्बोनाइजेशन से उत्सर्जन में कमी

वेदांता के मुताबिक, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने और डिकार्बोनाइजेशन से जुड़े दूसरे उपायों की वजह से वित्त वर्ष 2021 से अब तक करीब 3.6 करोड़ टन CO_2e उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है। इसके अलावा, वेदांता के मेटल्स और माइनिंग कारोबार से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले करीब 14% की कमी आई है।

भारत का 2030 तक 500 GW का लक्ष्य

भारत ने भी रिन्यूएबल और नॉन-फॉसिल फ्यूल वाली ऊर्जा को बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। देश का लक्ष्य 2030 तक 500 GW की नॉन-फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर कैपेसिटी हासिल करना है। इसके अलावा भारत 2030 तक अपनी टोटल एनर्जी जरूरतों का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना चाहता है। देश ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने के लिए सिर्फ सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगाना ही काफी नहीं होगा। इसके साथ ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर ग्रिड, एनर्जी स्टोरेज और इलेक्ट्रिफिकेशन में भी बड़े स्तर पर निवेश करना होगा।

मेटल्स और मिनरल्स की बढ़ सकती है मांग

रिन्यूएबल एनर्जी और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में बड़ी मात्रा में मेटल्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। ऐसे में जैसे-जैसे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, वैसे-वैसे इन मेटल्स और मिनरल्स की मांग भी लंबे समय तक बढ़ सकती है। यही वजह है कि रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती जरूरत आने वाले सालों में मेटल्स और माइनिंग कंपनियों के लिए भी कारोबार के नए अवसर पैदा कर सकती है।